

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९७६

मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६

विषय-सूची

आरार:-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. अनुसूची का संशोधन.
४. पोषण, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां.
५. आदेशों का प्रकाशन तथा तामील.
६. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
७. साक्षितियां.
८. प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण.
९. नियमों द्वारा अपराध.
१०. अपराधों का संज्ञान.
११. अपराधों का संश्लेषण: विचारण करने की शक्ति.
१२. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१३. नियम बनाने की शक्ति.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९७६.

मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६

दिनांक ६ मार्च १९७६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २७ मार्च १९७६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई 1.

पशुओं के पोषण तथा संभलन का जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के सत्ताहस्तों वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६ है.

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जिन्हें/जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "पशु" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये पशुओं में से कोई पशु;

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या रजिस्ट्रार किया गया कोई निगमित निकाय तथा उसके अन्तर्गत कोई कम्पनी, फर्म या व्यष्टियों की अन्य संस्था आती है;

(ग) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत है उस फर्म का कोई प्राणीदार;

(घ) "अधिसूचित आदेश" से अभिप्रेत है राजपत्र में अधिसूचित किया गया कोई आदेश.

३. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किये जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जायगी.

अनुसूची का
संशोधन.

पोषण, प्रदाय, सुविधा या लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में किसी पशु को रखे जाने, उसका पोषण या संचलन किया जाने का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगी।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन दिये गये किसी आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे :—

- (क) पशुओं को बांधने या डकट्टा करने का, उनकी संख्या की तथा उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थान की दृष्टि से, प्रतिषेध करने या विनियमन करने के लिए;
- (ख) पशुओं का निरीक्षण करने के लिए तथा दुग्धशालिक या दुग्ध विक्रेता का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के अधिभोग में के दुग्धालयों तथा पशु-सायबानों के सन्निर्माण, परिमाण, संवातन, प्रकाश, सफाई, जल-निकास तथा जल प्रदाय का विनियमन करने के लिए;
- (ग) ग्वाला बस्तियों (कालोनी), दुग्धालयों तथा पशु-बाड़ों की स्थापना या सन्निर्माण के लिए;
- (घ) विनिर्दिष्ट स्थान या क्षेत्र में पशुओं के आयात के प्रतिषेध या विनियमन के लिए;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन के विषयों में से किसी भी विषय का अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र द्वारा या अन्यथा विनियमन करने के लिये;
- (च) फीस के प्रभारण को सम्मिलित करते हुए किन्हीं भी आनुषंगिक या अनुपूरक विषयों के लिए।

आदेशों का प्रकाशन तथा तामील.

५. (१) धारा ४ के अधीन किया गया कोई आदेश,—

- (क) उस दशा में जबकि वह सामान्य प्रकार का आदेश हो या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाला आदेश हो, राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा;
- (ख) उस दशा में जबकि वह आदेश किसी एकल व्यक्ति या किसी एकल निगम को प्रभावित करने वाला आदेश हो, विहित रीति में तामील किया जायगा।

(२) जहाँ कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को धारा ४ के अनुसरण में किये गये किसी आदेश की सम्पर्क रूप से इतिहास दी गई थी, वहाँ उपधारा (१) की या उसके अधीन बनाये गये नियमों की उपधाराओं का अनुमानन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उसे ऐसी इतिहास दी गई थी। किन्तु जहाँ उपधाराओं का अनुमानन न करना किन्हीं अन्य साक्ष्यों से यह साबित करने का कि उसे उस प्रकार इतिहास दी गई थी प्रचारण नहीं करेगा और न उस आदेश की विधिमान्यता को ही प्रभावित करेगा।

६. राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती कि धारा ४ के अधीन आदेश करने की शक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा भी या स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी तथा ऐसे विषयों के संबंध में तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जैसा कि उस अधिसूचित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रयोज्य होगी।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

७. (१) यदि कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती, या जुर्माने से दंडित किया जायगा।

शक्तियाँ।

(२) किसी आदेश के उल्लंघन का विचारण करने वाला कोई भी न्यायालय यह निदेश दे सकता कि कोई ऐसा पशु, जिसके कि वारे में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, तथा कोई ऐसा बोन या जलयान या पशु, जिसके कि वारे में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की जानकारी से उसका उपयोग ऐसे पशु का बहन करने के लिए किया गया है, सरकार के पक्ष में समपुष्ट कर लिया जाय।

८. किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो कि धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उसके उल्लंघन को दुष्प्रति करता है, यह समझा जायगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।

प्रयत्न तथा
दुष्प्रति।

९. (१) यदि धारा ४ के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई निगम है, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उल्लंघन के समय उस निगम के कामकाज के संचालन के लिए उस निगम के प्रति वचनबद्ध था, उस निगम का भार-साधक था और उस निगम के प्रति उत्तरदायी था, तथा साथ ही उस निगम को भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वे इस बात के भागी होंगे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उन्हें दंडित किया जाय।

निगमों द्वारा
अपराध।

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या कि उसने ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी निगम द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध निगम के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की समझ या भौतानुकूलता से किया गया है या कि कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा की गई कोई अपेक्षा उस अपराध का कारण मानी जा सकती है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार इस बात का भागी होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उसे दण्डित किया जाय।

१०. (१) ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय, उन तथ्यों के संबंध में, जिससे कि अपराध बनता है, की गई लिखित रिपोर्ट के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अपराधों का
संज्ञान।

(२) राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी, जो कि प्राधिकृत किया जाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, किन्हीं कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के या तो पूर्व या पश्चात्, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर कि ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया हो, अपराध के सम्पन्न के सन्दर्भ एक हजार रुपये से अधिक धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकेगा तथा यह निर्देश दे सकेगा कि उसके द्वारा प्राप्ति किब गये उसके (एन, यात या जलयान के) मूल्य से अधिक ऐसी धनराशि को, जिसे कि वह सचित समझे, भुगतान हो जाने पर, उसे पण, धान या जलबान को, जो कि इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न किये जाने के दामित्वाधीन होने के नाते अभिग्रहीत किया गया हो, निरुक्त कर दिया जाव.

(३) उपधारा (२) के अधीन तथा उपबोधित समन-धन तथा प्रतिरक्षा धनराशि का ऐसे अधिकारी को भुगतान हो जाने पर वह व्यक्ति, यदि अधिकारी में हो, छोट्टि दिना कार्यवा और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी दायिक न्यायालय में संस्थित की गई हो, तो समन का धन दोषमुक्त तदमा जायगा और उसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति या पण, धान या जलयान के विरुद्ध और धान की कोई भी कार्यवाही किसी भी दशा में नहीं की जायगी.

(४) किसी अपराध का समन करने वाला अधिकारी किसी ऐसी अनुसूचित या अनुज्ञापित के जो कि अपराध को इस अधिनियम के अधीन दिया गया हो, रद्द करण का आदेश दे सकेगा, या यदि वह अधिकारी ऐसा करने के लिये मशवत न हो, तो वह इस प्रकार मशवत किये गये किसी अधिकारी के पारा ऐसी अनुसूचित या अनुज्ञापित के रद्दकरण के लिए जा सकेगा.

अपराधों को संश्लेषित विचारण करने की शक्ति.

११. बड़ प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ संव १९७४) की धारा २६० की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये अपराधों का संश्लेषित विचारण करने के लिये संश्लेषित विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता या इस अधिनियम में प्रावेदन किया जाने पर, किसी भी ऐसे अपराध का, जो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हो, उक्त संहिता की धारा २६२ से २६४ तक में असाधित उपबन्धों के अनुसार विचारण कर सकेगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.

१२. (१) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए, जो कि धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सहायपूर्वक की गई हो या जिसका सहायपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अधिवक्ता या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

(२) किसी भी ऐसा बात के द्वारा, जो धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सहायपूर्वक की गई हो या जिसका सहायपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, सहाय गये या सहायक सहाय्ये जाने वाले किसी मूलभूत के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१३. (१) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

अनुसूची

- (१) झाड़
- (२) जेल
- (३) गाय
- (४) कलौर
- (५) दछड़े
- (६) भैंस
- (७) बकरी
- (८) भेड़

भोपाल, दिनांक २७ मार्च १९७६.

क्र. १२२८६-एनकीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २१ सन् १९७६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सं. झु. सुराणा सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 1976.

THE MADHYA PRADESH PASHU (NIYANTRAN)
ADHINIYAM, 1976

[Received the assent of the Governor on the 9th March, 1976; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 27th March, 1976.]

An Act to provide in the interests of the general Public for the maintenance and movement of cattle.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twentieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Pashu (Niyantaran) Adhiniyam, 1976.

Short title,
extent and
commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date and in such areas as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "cattle" means any of the animals specified in the Schedule;

(b) "corporation" means any body corporate constituted or registered under any enactment for the time being in force and includes a company, firm or other association of individuals;

(c) "director" in relation to a firm means a partner in the firm;

(d) "notified order" means an order notified in the official Gazette.

3. The State Government may, by notification in the official Gazette, add to or alter or amend the Schedule and on such notification being issued, the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

Amendment of
Schedule.

4. (1) If the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for the purpose of promoting the public safety or public convenience or public health, it may, by a notified order, prohibit or regulate the keeping, maintaining or movement of any cattle in any particular place or area specified in such order.

Powers to control
maintenance,
supply, distribu-
tion, etc.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), and an order made thereunder may provide—

(a) for prohibiting or regulating stalling or herding of Cattle in regard to the number thereof, and the place to be used for the purpose;

(b) for the inspection of the cattle and regulating the construction, dimension, ventilation, lighting, cleaning, drainage and water supply of dairies and cattle sheds, in the occupation of persons following the trade of dairy men or milk seller;

(c) for establishment or construction of Gwala colonies, dairies and cattle pens;

(d) for prohibition or regulation of import of cattle in the specified place or area;

(e) for regulating by licence, permit or otherwise any of the matters under the Act;

(f) for any incidental or supplementary matters, including the charging of the fees.

Publication and
service of orders.

5. (1) An order made under section 4 shall—

(a) if it is an order of general nature or affecting a class of persons, be notified in the official Gazette;

(b) if it is an order affecting an individual person or an individual corporation be served in the prescribed manner.

(2) Where a question arises whether a person was duly informed of an order made in pursuance of section 4, compliance with the requirements of sub-section (1) or the rules made thereunder shall be conclusive proof that he was so informed, but failure to comply with the said requirement shall not preclude proof by other means that he was so informed or affect the validity of the order.

Delegation of
powers.

6. The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders under section 4 shall be exercisable also by such officer or authority including local authority and in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the order.

Penalties.

7. (1) If any person contravenes any order made under section 4, he shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

(2) Any Court trying the contravention of an order may direct that any cattle in respect of which the Court is satisfied that the order has been contravened, and any vehicle or vessel or animal which the Court is satisfied has been used with the knowledge of the person having the control thereof for carrying such Cattle, shall be forfeited to Government.

8. Any person who attempts to contravene, or abets a contravention of, any order made under section 4 shall be deemed to have contravened that order. Attempts and Abetment.

9. (1) If the person contravening an order made under section 4 is a corporation, every person, who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to the corporation for the conduct of the business of the corporation as well as the corporation, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly : Offences and corporations.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a corporation and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the corporation such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

10. (1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a report in writing of the facts constituting such offence made by such officer as may be authorised by the State Government. Cognizance of offences.

(2) The State Government or such officer as may be authorised may, either before or after the institution of any proceedings for any offence punishable under this Act, accept from any person charged with such offence by way of composition of the offence a sum of money not exceeding one thousand rupees, and direct the release of cattle, vehicle or vessel, which has been seized as liable to forfeiture under this Act, on payment of such further sum of money as he may deem fit not exceeding the value thereof estimated by him.

(3) On payment of the composition money and additional sum of money, as provided under sub-section (2), to such officer, the person, if in custody, shall be set at liberty and if any proceedings have been instituted against such person in any criminal court, the composition shall be deemed to amount to an acquittal and in no case shall any further proceedings be taken against such person or cattle, vehicle or vessel in respect of the same offence.

(4) The officer compounding any offence may order the cancellation of any licence or permit granted under this Act to the offender, or if not empowered to do so, may approach an officer so empowered, for the cancellation of such licence or permit.

Power to try
offence summarily.

11. Any Magistrate of the first class specially empowered for the time being to try in a summary way the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code any offence punishable under this Act.

Protection of
action taken
under Act.

12. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 4.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 4.

Power to make
rules.

13. (1) The State Government, may, by notification, and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) The rules made under sub-section (1) shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

Schedule

1. Bulls.
2. Bullocks.
3. Cows.
4. Heifers.
5. Calves.
6. Buffaloes.
7. Goats.
8. Sheep.